



रज़िर्व बैंक की स्वायत्तता पर नहीं आनी चाहयि कोई आँच

संदर्भ

रज़िर्व बैंक के गवर्नर उरजति पटेल ने जब 10 दसिंबर को इस्तीफा दिया, तो एकबारगी सभी हैरान रह गए। अचानक आए इस इस्तीफे ने बाज़ार और सरकार में खलबली मचा दी थी। लेकिन इसके अगले ही दिन भारत सरकार ने आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास को तीन साल के लिये RBI का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया, जबकि सामान्यतया ऐसी परस्थिति में रज़िर्व बैंक के डपिटी गवर्नर को कुछ समय के लिये ज़िम्मेदारी दी जाती है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से रज़िर्व बैंक और केंद्र सरकार के बीच केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता के मसले को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। नए गवर्नर शक्तिकांत दास ने स्वायत्तता को ज़रूरी बताते हुए सरकार के साथ सहयोग करने की बात कही है।

क्यों उठा रज़िर्व बैंक की स्वायत्तता का मुद्दा?

रज़िर्व बैंक के नवनिर्भर गवर्नर ने पदभार संभालने के बाद जब यह कहा कि केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता और गरिमा बनाए रखी जाएगी, तो यह स्पष्ट था कि दाल पूरी काली नहीं, तो भी इसमें कुछ काला अवश्य ही है। इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी स्वीकार किया कि कुछ मुद्दों पर रज़िर्व बैंक के साथ मतभेद हैं।

रज़िर्व बैंक और सरकार के बीच तनाव के मुद्दे पर डपिटी गवर्नर वरिल आचार्य कह चुके हैं कि केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को कमजोर करना 'बेहद वनिशकारी' हो सकता है। सरकार में बैठे लोग रज़िर्व बैंक से कमजोर बैंकों के लिये कर्ज़ लेने के नियमों को आसान बनाने की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही, रज़िर्व बैंक के नयामक अधिकारों में कटौती कर एक नई भुगतान नयामक एजेंसी भी बनाने की बात चल रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर रज़िर्व बैंक और सरकार के बीच रस्साकशी चल रही है।

धारा 7 का मुद्दा भी आया सामने

इसके अलावा पूर्व गवर्नर RBI एक्ट की धारा 7 को लेकर भी सरकार से असहमत थे। RBI एक्ट की धारा 7 की तीन प्रमुख उप-धाराएँ हैं:

- सेक्शन 7(1):** इसके तहत केंद्र सरकार रज़िर्व बैंक के गवर्नर से परामर्श कर बैंक को ऐसे दशा-नरिदेश दे सकती है, जो जनता के हित में आवश्यक हों।
- सेक्शन 7(2):** इसके तहत इस तरह के किसी भी दशा-नरिदेश के बाद बैंक का काम एक केंद्रीय नदिशक मंडल को सौंप दिया जाएगा। यह नदिशक मंडल बैंक की सभी शक्तियों का उपयोग कर सकता है और रज़िर्व बैंक द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों को कर सकता है।
- सेक्शन 7(3):** इसके तहत रज़िर्व बैंक के गवर्नर और उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामित डपिटी गवर्नर की गैर-मौजूदगी में भी केंद्रीय नदिशक मंडल के पास बैंक के सामान्य मामलों एवं कामकाज के सामान्य अधीक्षण (General Superintendence) एवं नरिदेशन की शक्तियाँ होंगी और वह उन सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएगा, जसि करने का अधिकार बैंक के पास है।

दरअसल, रज़िर्व बैंक ने 12 बैंकों को इस्टैंट एक्शन की कैटेगरी में डाल दिया था। इससे बैंकों के नए कर्ज़ देने, नई ब्रांच खोलने और डविडिंड देने पर प्रतबंध लग गया। मुद्दे ने तब और तूल पकड़ा, जब सरकार ने RBI से अधिक डविडिंड देने को कहा और आपातस्थिति के लिये अतिरिक्त रज़िर्व रखने की ज़रूरत पर सवाल उठाया। सरकार की ओर से RBI के कामकाज में बड़ा दखल उस समय सामने आया था जब सरकार ने RBI के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की समीक्षा करने की मांग की थी। इसके साथ ही सरकार का कहना था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा लिये जाने वाले फैसलों में उसकी भूमिका बढ़नी चाहिये।

क्या होगा तनातनी का असर?

केंद्र सरकार और रज़िर्व बैंक के बीच चल रही तनातनी अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम फैसले लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। खासतौर पर ऐसे वक़्त में जब भारत का वित्तीय बाज़ार बड़े बुनयादी निर्माण के लिये धन देने वाली कंपनियों के कर्ज़ भुगतान में नाकामी के कारण संकट में है। इसकी वज़ह से पूरे नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में तरलता (Liquidity) की कमी आ सकती है। ऐसे में सरकार और रज़िर्व बैंक के बीच शीर्ष स्तर पर असंतोष की वज़ह से अस्थिरता की आशंका बनी रहेगी, जसिका असर अर्थव्यवस्था और बाज़ार पर भी पड़ सकता है।

रज़िर्व बैंक के बारे में कतिना जानते हैं आप?



भारतीय रज़िर्व बैंक के क्रमिक विकास, एकीकरण, नीतितगत बदलावों और सुधारों की एक लंबी और कठिनी यात्रा रही है, जसिने इसे संस्थान के रूप में एक अलग पहचान दी है। रज़िर्व बैंक की स्थापना के लिये सबसे पहले जनवरी, 1927 में एक वधियक पेश कयिा गया और सात वर्ष बाद मार्च, 1934 में यह अधनियिम बना। 1935 में रज़िर्व बैंक की स्थापना से पहले केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यकलाप प्राथमिकि तौर पर भारत सरकार द्वारा संपन्न कयिे जाते थे। कुछ हद तक ये कार्य 1921 में अपनी स्थापना के बाद भारतीय इम्पीरियल बैंक द्वारा संपन्न होते थे। नोट जारी करने हेतु नयिमन, वदिशी वनियिम का प्रबंधन एवं राष्ट्र की अभरिकाषा और वदिशी वनियिम भंडार जैसे कार्यों की ज़मिमेदारी भारत सरकार की होती थी। इम्पीरियल बैंक सरकार के बैंक के रूप में काम करता था और व्यावसायिक बैंक के रूप अपनी प्राथमिकि गतिविधियों के अलावा यह एक हद तक बैंकों के बैंक के रूप में भी काम करता था। जब रज़िर्व बैंक की स्थापना हुई, तब भारत में संस्थागत बैंकगि का विकास होना शुरू हुआ।

ये तो थी पुराने दनिों की बात, आज रज़िर्व बैंक एक ऐसे संस्थान के रूप में काम कर रहा है, जो मौद्रिकि स्थायित्व, मौद्रिकि प्रबंधन, वदिशी वनियिम, आरकषति नधिप्रबंधन, सरकारी करज प्रबंधन, वतितीय नयिमन एवं नगिरानी सुनश्चिति करने का काम करता है। इसके मुख्य दायित्वों में मुद्रा प्रबंधन और भारत के हक में इसकी साख व्यवस्था का संचालन भी शामिल है।

नए गवर्नर के सामने प्रमुख चुनौतियाँ

भारतीय रज़िर्व बैंक के नए गवर्नर शकृत्किंत दास के सामने न सरिफ़ पूरव गवर्नर उरजति पटेल के अधूरे कामों का भारी-भरकम एजेंडा है बल्कि उनहें RBI की साख सुधारने की बड़ी ज़मिमेदारी भी नभानी होगी।

1. शकृत्किंत दास के सामने सबसे बड़ी चुनौती रज़िर्व बैंक की साख को बचाने की है। उनहें सरकार के साथ चल रही तनातनी को खत्म कर केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता सुनश्चिति करनी होगी। गौरतलब है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सभी देशों के केंद्रीय बैंकों की भूमिका बेहद महत्त्वपूर्ण होती है और अपनी सरकारों से स्वायत्त रहना इनके लिये आदर्श स्थिति होती है।
2. रज़िर्व बैंक के गवर्नर को तीन साल के लिये नयुक्त कयिा जाता है। रज़िर्व बैंक के नए गवर्नर के सामने एक चुनौती यह भी होगी कि वह तीन साल के अपने कार्यकाल के दौरान घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थितिके आधार पर मौद्रिकि नीति निर्धारति करें और केंद्र सरकार से बेहतर सामंजस्य स्थापति करें।
3. पूरव के गवर्नरों ने केंद्र सरकार द्वारा RBI में बदलाव का वरिोध कयिा है। बीते कुछ समय से केंद्रीय बैंक ने देश में बैंकगि कषेत्तर की अपनी नीतियों को कड़ा कयिा है और इसके चलते सरकारी बैंकों का करज लेने और देने का काम प्रभावति हुआ है। साथ ही बैंकों के NPA में सुधार की नीतियों को संचालति करना भी नए गवर्नर के सामने एक बड़ी चुनौती है।
4. केंद्र सरकार के सामने महँगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। महँगाई को अहम आधार बनाते हुए केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों निर्धारति करता है। बैंकों की ब्याज दरों को बढ़ाना या घटाना देश में और वैश्विक स्तर पर महँगाई की दर को भी आधार बनाकर तय कयिा जाता है। बीते चार साल के दौरान देश को कच्चा तेल कम कीमतों में मलिन से भारी राहत मली थी, जसिकी वज़ह से केंद्र सरकार और RBI के लिये महँगाई को काबू में रखना आसान हो गया था। ऐसे में वैश्विक स्थिति विपरीत होने पर महँगाई को काबू में रखना RBI के सामने अहम चुनौती होगी।
5. केंद्र सरकार से स्वायत्तता के मुद्दे पर स्पष्टता और बेहतर मौद्रिकि नीतिके साथ-साथ मौजूदा घरेलू आर्थिक स्थिति और वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना भी रज़िर्व बैंक के गवर्नर के सामने एक अहम चुनौती है। इसके अलावा, देश में बड़े निवेश को बढ़ावा देना, वैश्विक अर्थव्यवस्था में कारोबारी सुगमता के मापदंड पर बेहतर प्रदर्शन करना और घरेलू कारोबार को बढ़ाने के लिये उचित नीतियों का सहारा लेना केंद्रीय बैंक के लिये बेहद चुनौतीपूर्ण होगा।

RBI की स्वायत्तता पर सरकार का पक्ष

रज़िर्व बैंक से हुए विवाद के चलते केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर को एक प्रेस वजिप्त जारी कर स्पष्टीकरण दयिा था:

“RBI अधनियिम की रूपरेखा के तहत केंद्रीय बैंक के लिये स्वायत्तता का होना गवर्नेंस से जुड़ी एक अनविर्य एवं अवविदति आवश्यकता है। वभिन्न सरकारों ने इसे ध्यान में रखा है और इसका सम्मान कयिा है। सरकार एवं केंद्रीय बैंक दोनों ही अपने कामकाज में जनहति और भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से नरिदेशति होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए समय-समय पर सरकार और RBI वभिन्न मुद्दों पर वसितार से सलाह-मशवरी करते हैं। भारत सरकार इसकी वषिय-वस्तु को सार्वजनिकि नहीं करती और अंतिम नरिणयों के ही बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है।

स्रोत: Hindu Business Line, PIB